बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 69

फिर छिड़ी कारोबारी जंग

अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग की आग फिर भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से होने वाले करीब 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 10 फीसदी से 25 फीसदी कर देंगे। इसके अतिरिक्त 32,500 करोड़ डॉलर मूल्य के अतिरिक्त आयात पर भी जल्दी ही शुल्क दर को बढ़ाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। ट्रंप लंबे समय से कहते रहे हैं कि चीन से होने वाले आयात पर शुल्क दर बहुत कम है। उन्होंने ट्विटर पर एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि अब चीन को इन दरों के चलते अमेरिकी राजकोष में सैकड़ो करोड़ डॉलर की राशि जमा करनी पड़ रही है। हालांकि यह बात सही नहीं है। यह शुल्क, आयात करने वाली कंपनियों द्वारा सीमा पर चुकाया जाता है। अधिकांश आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि इसका ज्यादातर बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत के रूप में चुकाना पड़ रहा है या फिर अमेरिकी कंपनियां अपना मार्जिन कम करके इसकी भरपाई कर रही हैं। अभी यह निश्चित नहीं है कि ट्रंप अपनी चुनौती पर आगे कार्रवाई करेंगे या नहीं।

यद्यपि बाजार का मानना है कि कि चीन-अमेरिका के बीच कारोबारी युद्ध जल्द समाप्त नहीं होने वाला है। उसने इसे लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बहुत संभव है कि यह बातचीत की शर्तें तय करने का ट्रंप का तरीका हो लेकिन भविष्य में विसंगति उत्पन्न होने की आशंका तो है। यह सही है कि अमेरिका में अब आम राजनीतिक समझ यही है कि चीन पर दबाव बनाया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर उसका रवैया बदले, खासतौर पर अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की चोरी को लेकर हाल के दिनों में काफी चिंता जताई गई है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक ओर जहां टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका के सहयोगी और साझेदार मुल्कों में लोकप्रिय नहीं है, वहीं कई देशों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि व्यापारिक व्यवस्था को और अधिक बराबरी वाली बनाना होगा ताकि चीन इसका अनुचित लाभ न ले सके।

भारत के लिए यह जोखिम और अवसर दोनों साथ लाया है। अगर भारतीय निर्यातक चीन के गलत व्यवहार से प्रेरित तरीकों में उलझते रहे तो यह जोखिम की बात है। खेद की बात है कि भारत, जिसकी चीन के साथ कारोबार को लेकर अपनी अलग दिक्कतें हैं, उसने न तो अमेरिका को संतुष्ट किया है और न ही यूरोपीय संघ या जापान को। संभव है कि विकसित विश्व की ओर से ऐसा दबाव बने कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के तहत मिल रहे लाभ की पेशकश खत्म कर दी जाए। भारत पर इसका नकारात्मक असर होगा, भले ही वह चीन से पांच गुना गरीब है। इस मसले को हल करने के लिए तत्काल व्यापारिक कूटनीति की आवश्यकता है। भारत को आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिका में बदलता माहौल भारतीय निर्यात को प्रभावित न करे। पहले ही प्राथमिकता की व्यवस्था समाप्ति की प्रक्रिया में है और एच-1बी वीजा पाना और भी कठिन हो गया है।

भारत को अपने यहां संरक्षणवादी उपायों को लेकर भी सजग रहना होगा। घरेलू मोबाइल विनिर्माण, ई-कॉमर्स पर कड़ाई, सरकारी सोर्सिंग नियमन और डेटा का स्थानीयकरण ऐसे ही मुद्दे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा है कि भारत ने निरंतर अनुरोध के बाद भी प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों को शिथिल करने की पहल नहीं की है। अगर भारत इस नए माहौल का लाभ वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में कर सकता है तो उसके पास नए रोजगार तैयार करने के अवसर हैं। बीते कुछ वर्ष में इसकी भारी कमी महसूस की गई।

अजय मोहंती

फंसे हुए कर्ज के समाधान के दिलचस्प मामले

इस हफ्ते कर्ज भुगतान में चूक करने वाली दो कंपनियों के दिवालिया समाधान के बारे में एनसीएलटी का फैसला आने की संभावना है। इससे अवगत करा रहे हैं **तमाल बंद्योपाध्याय**

भारत के दिवालिया समाधान कानून के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) अगले कुछ दिनों में 6,113 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कर्ज से संबंधित दो मामलों का निपटारा कर सकता है। इन दोनों ही कंपनियों पर सबसे ज्यादा बकाया कर्ज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का है। पंजाब नैशनल बैंक, कैनरा बैंक और आंध्रा बैंक ने भी इन कंपनियों को अच्छा-खासा कर्ज दिया हुआ है।

इन दोनों कंपनियों का नाम वाणिज्यिक बैंकों को भेजी 28 चूककर्ता कंपनियों की उस सूची में भी शामिल था जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर 2017 के अंत तक एनसीएलटी में ले जाने को कहा था। आरबीआई ने कहा था कि अगर दिसंबर 2017 के मध्य तक ये कंपनियां बकाया कर्ज का भुगतान नहीं करती हैं तो फिर उन्हें एनसीएलटी कार्यवाही का सामना करना होगा। आरबीआई ने जून 2017 में 12 बड़ी चूककर्ता कंपनियों की पहली सूची जारी की थी जिनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी थी। उसके बाद आरबीआई ने अगस्त के अंत में संकटग्रस्त कंपनियों की दूसरी सूची भी सौंपी थी। ये ऐसे खाते थे जिनकी 60 फीसदी बकाया राशि को 30 जून 2017 तक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया जा चुका था। इन दोनों सूचियों में शामिल कुल राशि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में फंसे कर्जों का करीब आधा हिस्सा बन जाता है।

दिवालिया कानून के तहत किसी मामले का निपटान 180 दिन के भीतर करना होता है लेकिन उस सीमा को 270 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। एनसीएलटी के मुंबई पीठ में उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड और उत्तम गैल्वा मेटेलिक्स लिमिटेड कंपनियों के कर्ज समाधान की दो याचिकाओं को स्वीकृति दी थी। बैंकों को 270 दिनों की यह मियाद 3 अप्रैल को पूरी होने के बाद समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 दिन और मिले।

एक बार चूककर्ता के चिह्नित हो जाने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक समाधान पेशेवर (आरपी) की नियुक्ति करता है। अगले चरण में एक सूचना ज्ञापन तैयार किया जाता है और संभावित बोलीकर्ताओं से अभिरुचि पत्र देने को कहा जाता है। बोलीकर्ताओं की योग्यता का परीक्षण करने के बाद उनकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की पहचान की जाती है और तब सीओसी इसकी जानकारी एनसीएलटी को देता है। इन दोनों कंपनियों के समाधान पेशेवर नियुक्त हुए राजीव चक्रवर्ती (पीडब्ल्यूसी के पार्टनर) को इसी हफ्ते एनसीएलटी से इस समाधान योजना पर स्वीकृति लेनी है। सवाल है कि समाधान योजना क्या है और निविदा में किसने बाजी मारी है? ये दोनों मामले एकल खिड़की वाली दिवालिया समाधान प्रक्रिया की प्रगति को रेखांकित करते हैं जिससे संकट में फंसी परिसंपत्तियों के समाधान की लागत एवं समय कम करने की संभावना होती है।

विजेता टीम में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश करने वाली फर्मों कारवाल इन्वेस्टर्स और नीतिया कैपिटल रिसोर्सेज एडवाइजर्स के नाम शामिल हैं। उनकी बोली में कहा गया है कि कारवाल आर्सिल ट्रस्ट एआरसी नाम से एक ट्रस्ट बनाएगा जिसका 15 फीसदी फिलहाल भारत की सबसे पुरानी परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास है।

इन संकटग्रस्त कंपनियों में उत्तम वैल्यू स्टील्स की महाराष्ट्र के वर्धा में हॉट-रोल्ड की उत्पादन क्षमता करीब 10 लाख टन है। इसके लिए वह उत्तम गैल्वा मैटेलिक्स से पिग आयरन खरीदती है।

कारवाल खाद्य एवं कृषि उत्पादों की दिग्गज कंपनी कारगिल की निवेश इकाई है। वर्ष 2010 में गठित नीतिया कैपिटल लंदन की एक निवेश कंपनी है जिसकी कुल हैसियत 1,000 पौंड है। वर्ष 2018 में उसने 2.76 लाख पौंड का घाटा उठाया था।

विजेता बोलीकर्ताओं की तरफ से किए जाने वाले भुगतान के ढांचे एवं कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। उन्होंने 2,541 करोड़ रुपये की बोली लगाई है जिसमें से 625 करोड़ रुपये अग्रिम दिए जाने हैं। कर्जदाताओं को एक रकम मिल जाएगी लेकिन ये दोनों कर्जदार कंपनियों को 15 फीसदी ब्याज पर कर्ज के रूप में दी जाएगी। बाकी 1,200 करोड़ रुपये पांच वर्षों के भीतर दोनों कंपनियों के आंतरिक स्रोतों से पूरी की जाएगी। बोलीकर्ताओं का महंगा कर्ज चुकाने के बाद क्या ये कंपनियां इतना कमा पाएंगी कि बैंकों का बकाया लौटा सकें?

इस पैकेज में 198 करोड़ रुपये की कम-से-कम तीन साल के लिए कारोबार प्राप्तियां और बकाया भी हैं। इसके अलावा 248 करोड़ रुपये आपूर्तिकर्ताओं को करीब दशक भर पहले अग्रिम भुगतान के तौर पर दिए गए हैं। ये आपूर्तिकर्ता प्रवर्तकों- लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज और फ्रंटलाइन रॉल फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड की समूह कंपनियां हैं।

यह हिस्सा बैंकरों को किए जाने वाले भुगतान की योजना में शामिल है। अगर एक साल के भीतर बैंकों को यह रकम नहीं मिलती है तो उसे बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। कुछ व्यापार प्राप्तियां और अग्रिम कई वर्षों से लंबित हैं। आखिरकार 270 करोड़ रुपये राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में आएंगे। इस अनुदान की प्राप्ति को लेकर कई तरह की शर्तें जुड़ी हुई हैं।

परिचालक लेनदारों पर कंपनियों के 1,017 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्हें तीन करोड़ रुपये का उदार अंशदान का भी वादा किया गया है। बैंकों को 625 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया गया है, 2,541 करोड़ रुपये का नहीं। ऐसे में बैंकों को करीब 90 फीसदी तक का नुकसान (हेयरकट) उठाना पड़ेगा जबकि पहले 60 फीसदी का अनुमान जताया गया था।

इस अंतिम बोली के पहले कई दावे एवं प्रतिदावे सामने आए थे। सिनर्जी मेटल्स ऐंड माइनिंग फंड्स, एआरटी स्पेशल सॉल्यूशन फाइनेंशेज और इन्वेस्टमेंट ऑपरच्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम ने 3,300 करोड़ रुपये का समाधान प्रस्ताव पेश किया था लेकिन उसे नकार दिया गया था। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और लिबर्टी हाउस ग्रुप ने भी बोली लगाने की मंशा जताई थी लेकिन उन्हें रोक दिया गया।

अब ये सवाल रह गए हैं:

- करीब 10 अरब डॉलर की परिसंपत्ति का प्रबंधन करने वाली और तीन दशकों का अनुभव रखने वाली कारवाल ने महज 1000 पौंड परिसंपत्ति का प्रबंधन करने वाली नीतिया के साथ जोड़ी क्यों बनाई है?
- क्या नीतिया ने कर्जदाता बैंकों को यह बताया कि उसके चेयरमैन जोहानस सिटार्ड ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया? आर्सेलरमित्तल के लक्ष्मी मित्तल के विश्वस्त सहयोगी सिटार्ड ने शायद समाधान योजना रखने के बाद इस्तीफा सौंपा है।
- नीतिया कैपिटल के संस्थापक एवं सीईओ जय कृष्ण सराफ लंदन में रहते हैं। क्या वह 10 लाख टन क्षमता वाले स्टील संयंत्र को चला सकते हैं?
- समाधान योजना में सबसे पहले निवेशकों का पुनर्भुगतान करने की बात कही गई है। इससे क्या बैंकों का बकाया लौटाने की कंपनियों की क्षमता प्रभावित नहीं होगी?
- सबसे बड़ी लगाने वाले कंसोर्टियम को बेहतर पुनर्भुगतान प्रस्ताव रखने के बाद भी क्यों नकार दिया गया?

निविदा प्रक्रिया बंद होने के बाद भी नई बोलियां लेने से अनावश्यक देरी होती है और प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इससे मूल्य आकलन में मदद मिलती है। मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और कुछ अन्य इस समाधान प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इन दोनों कंपनियों का पूंजीकरण मूल्य करीब 1,350 करोड़ रुपये है जो समाधान प्रक्रिया के तहत बैंकों को दिए गए आश्वासन का करीब दोगुना है।

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक एवं जन स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

इस चुनावी मौसम में काम की खबरें क्यों हैं नदारद

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मैं जिस संगठन के साथ काम करती हूं, वह पर्यावरण एवं विकास पर केंद्रित पाक्षिक पत्रिका 'डाउन टु अर्थ' प्रकाशित करता है। इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है और न ही यह बाजार या वाणिज्य की पैदाइश है। यह हमारे आसपास की दुनिया, रोजमर्रा की जिंदगी और जीवन के बारे में जानकारी साझा करने का जरिया है ताकि हमें ऐसा ज्ञान हासिल हो जो हमें बदलाव लाने की शक्ति दे सके। जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम अपना मिशन छिपाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं लेकिन पत्रकार के रूप में हम जमीनी स्तर से आने वाली खबरों एवं घटनाओं को रिपोर्ट करने की दक्षता में तटस्थता कायम रखते हैं। हमारा आग्रह और राजनीति पूरी तरह मुक्त है, कॉर्पोरेट चमक-दमक के पर्दे में छिपी नहीं है। लेकिन हम दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें अंजाम देने के बारे में हम खुलकर चुनौती देते हैं।

आज मैं आपसे आज के भारत और आज की दुनिया में डाउन टु अर्थ और ऐसे दूसरे प्रकाशनों की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करना चाहती हूं। आज की दुनिया दूसरों के दोष ढूंढने वाली है और पहले कभी भी इस तरह नीचे गिरने की होड़ नहीं देखी गई है। देशों का बदतर रूप देखने को मिल रहा है, लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए नेता जहर उगल रहे हैं। इस द्वेषपूर्ण विमर्श के गर्द एवं गुबार में असली मुद्दे गुम होते जा रहे हैं। इस बहस में हम केवल इसी हद तक स्वतंत्र नजर आते हैं कि अब पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह गए सोशल मीडिया में हम भी अपना गुबार निकाल सकें। ऐसा कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं है जो सार्वजनिक रूप से कहने लायक और न कहने लायक बातों के बीच रेखा खींच सके।

ऐसी स्थिति में हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम नाकाम हो चुके हैं? क्या हमें अब भी यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम सार्वजनिक मत में कोई बदलाव ला सकते हैं? मायने रखने वाले असली मुद्दों पर ध्यान बनाए रखने की क्या वाकई हम उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। मेरा इस पर भी यकीन है कि इस दुनिया में हम आज जो कुछ भी देख रहे हैं उन असली खबरों की सुगबुगाहट को भी चीख में बदलने के लिए कोशिश करना हमारा दायित्व और काम दोनों है।

भारत में आम चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के बीच मैं इस बात को जोर देकर कह रही हूं। अगले कुछ दिनों में हमें एक नई सरकार मिलेगी या पुरानी सरकार को ही नया कार्यकाल मिल जाएगा। जो भी हो, सच यह है कि हमारे आज और आने वाले कल को प्रभावित करने वाले मसलों पर लिखने के लिए 'डाउन टु अर्थ' जैसी पत्रिकाओं का मौजूद होना जरूरी है।

इस चुनाव में हमने देखा है कि लोगों के लिए मायने रखने वाले असली मुद्दे चर्चा से पूरी तरह बाहर हैं। मसलन, अजीबोगरीब मौसम लाकर फसलों को बरबाद करने वाला जलवायु परिवर्तन, इस चुनौती से निपटने में किसानों को राहत नहीं देने वाली बीमा कंपनियां, किसानों को उनकी मेहनत के बराबर उपज की कीमत न मिल पाना, आजीविका एवं स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा प्रदूषण और देश के बड़े हिस्से में बनते सूखे के हालात जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

ऐसा लगता है कि कोई भी असली मुद्दा हमारी चिंता के केंद्र में ही नहीं रह गया है। असल में, इन मुद्दों को उठाने से लोगों को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया भी इन प्रवृत्तियों को नजरअंदाज करता है। नेता आज हमें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वे क्षेत्र-विशेष के लिए अहम स्थानीय मुद्दों को भुलाकर भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में चुनाव भी जहरीले बयानों और ध्रुवीकृत समाज बनकर रह गए हैं।

लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि भले ही इस चुनावी मौसम में अहमियत रखने वाले ये मुद्दे सुर्खियों में नहीं आ रहे हैं लेकिन खबरों के शब्दों में ये सर्वव्यापी हैं। चुनाव के इस दौर में ही हमें जमीन से आने वाली आवाजें सुनने को मिलती हैं। सभी समाचारपत्र कृषि से लेकर कारखाने तक के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए अपने बेहतरीन संवाददाताओं को भेजते हैं। यह इकलौता समय है जब हम जनता का रुदन सुन पाते हैं और अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट-दर-रिपोर्ट, इलाका-दर-इलाका लोग यही कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी के लिए मायने रखने वाले मुद्दे ही सबसे अहम हैं। रोजगार, आजीविका, पानी की कमी, सूखा, बेमौसम बरसात से फसलों का नुकसान और मुआवजे का अभाव, आवारा पशुओं की समस्या और जंगली जानवरों के हमले लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं। कई रिपोर्टों में यह पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह रिहायशी बस्तियों के पास कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं और स्थानीय कारखानों से होने वाले प्रदूषण के चलते आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है या उन बस्तियों में साफ-सफाई या पानी निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं है।

लिहाजा 2019 के इस चुनाव में भले ही ये आवाजें कम सुनने को मिली हैं, लेकिन वे गुम नहीं होंगी। आजीविका और वजूद बचाए रखने के असली मुद्दे गायब नहीं होंगे। उन्हें न तो निगला जा सकता है और न ही बाहर फेंका जा सकता है। वे असली मुद्दे हैं। वे अहमियत रखते हैं। ऐसे में बदलाव के लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए इकलौता विकल्प यही है कि हाशिये पर धकेल दी गई खबरों को मुख्यधारा में लाना सुनिश्चित करें।

दूसरा सवाल अधिक बुनियादी प्रकृति का है। समाज के अधिक ज्ञानपरक एवं सरकारों के अधिक असहिष्णु होते जाने के दौरान हम सूचना की तलाश किस तरह जारी रख पाते हैं? मुझे लगता है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तथ्यों की विश्वसनीयता और स्थिति की स्वतंत्रता बनाए रखें। यह हमारी साझा चुनौती है जिसमें सफलता की मैं उम्मीद करती हूं।

कानाफूसी

हर्षवर्धन के बोल

अगर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हर्षवर्धन की बात पर यकीन करें तो हमारे शरीर को 45 मिनट से अधिक नींद की जरूरत नहीं होती। पेशे से चिकित्सक हर्षवर्धन ने सोमवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को ध्यान और अन्य प्रक्रियाओं के जरिये लंबे समय तक के लिए सुला सके तो उसके लिए 45 मिनट की नींद पर्याप्त होगी। वह चुनावी मौसम में अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह रोज 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सामान्य समझ को चुनौती दी है। गत वर्ष उन्होंने कहा था कि मशहूर भौतिकीविद स्टीफन हॉकिंग ने भी यह स्वीकार किया था कि वेदों के सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के ई=एमसी स्क्वायर के मशहूर समीकरण से बेहतर हैं। हालांकि वह इसका स्रोत नहीं बता पाए थे।

'साध्वी' स्वरा भास्कर

क्या अभिनेत्री स्वरा भास्कर राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं? पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची स्वरा ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया। एक कार्यक्रम में शामिल होने आई स्वरा ने कहा, 'अगर मैं भी भगवा साड़ी पहन लूं तो क्या लोग मुझे भी साध्वी कहकर पुकारेंगे? क्या यह संभव है?' हालांकि वह सक्रिय राजनीति में नहीं हैं लेकिन वह ट्विटर आदि सोशल मीडिया मंचों पर सरकार की निरंतर आलोचना करती रहती हैं। अप्रैल में उन्होंने बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया था।

आपका पक्ष

देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था

पिछले एक महीने से देश में चल रहे चुनाव के कारण जमीनी मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में शिक्षा व्यवस्था की मार लाखों छात्रों को झेलनी पड़ रही है। तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की सरकार में 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यह पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। वहां की सरकार ने एक निजी कंपनी को परीक्षा की कॉपियों की जांच का जिम्मा सौंपा था। कुल 9.74 लाख कॉपियों में से करीब 3.28 लाख कॉपियों में कई तकनीकी खामियां पाई गईं जिससे बहुत से छात्रों के अंकों में हेराफेरी की घटनाएं सामने निकल कर आईं। आखिरकार, 22 छात्रों की जान जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों के बढ़ते आक्रोश के कारण सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी। लेकिन सवाल यह है कि इतने व्यापक स्तर पर सरकारी विफलता का खमियाजा छात्र भुगत रहे हैं। दूसरी ओर देश की हिंदी

पट्टी राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में 10 लाख के करीब छात्र हिंदी विषय में फेल हो गए। दसवीं के 5.74 लाख, 12वीं के करीब 4.23 लाख फेल छात्रों के नाम सूची में शामिल हैं। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि हो सकता है कि छात्रों ने इन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया हो। पिछले

केंद्र तथा राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए

साल बिहार बोर्ड में भी परीक्षाफल के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तब उस वक्त की मौजूदा नीतीश सरकार की देश भर में काफी किरकिरी हुई थी। सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर परीक्षा के पैटर्न से लेकर कॉपी जांचने के पैटर्न में कुछ बदलाव लाए। शिक्षा के प्रति सजग प्रयास के चलते मौजूदा साल में 10वीं में करीब 81 फीसदी छात्रों ने परीक्षा पास की जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बेहतर परिणाम माना जा रहा है। अगर सरकारें शिक्षा के प्रति इस तरह उदासीनता नहीं दिखाएं तो हर साल फेल होने और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है।

उद्देश्य कुमार, मणिपाल

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का असर वैश्विक बाजारों पर साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल में कहा कि अमेरिका करीब 200 डॉलर मूल्य की चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद बाजार में व्यापक असर पड़ा और सेंसेक्स तथा निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले अमेरिका ने ईरान से तेल आयात पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान के कारण चीन के बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंध के कारण वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। इसका खमियाजा विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान पर प्रतिबंध लगाने से कच्चे तेल के सबसे बड़ा उत्पादक देश से निर्यात प्रभावित होगा। इससे कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में भारत ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। इसका भुगतान डॉलर में होता है लेकिन प्रतिबंध के कारण आयात प्रभावित होगा और भारत को नुकसान होगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।